भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 640
25 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

मांस प्रसंस्करण उद्योग

640. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मांस प्रसंस्करण उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मांस प्रसंस्करण उद्योगों और मांस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई योजना है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)
(क) उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण, 2016-17 के अनुसार मांस के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण हेतु 183 पंजीकृत यूनिटें हैं । पंजीकृत यूनिटों की राज्य-वार संख्या **संलग्नक** में दी गई है ।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मांस समेत कृषि-उपज के प्रसंस्करण के लिए यूनिटों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) की एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रहा है । सीईएफपीपीसी स्कीम के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% और सिक्किम एवं दूर्गम क्षेत्रों नामतः हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड), राज्य अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों तथा द्वीप समूहों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 50% परंतु प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी दी जाती है ।

वाणिज्य विभाग में, जिसके पास निर्यात संवर्धन का अधिदेश है इस समय मांस निर्यात के संवर्धन हेतु कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है ।

******

संलग्नक

मांस प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में दिनांक 25.06.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 640 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

मांस के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण हेतु पंजीकृत यूनिटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य	**फैक्ट्रियों/यूनिटों की संख्या**
आंध्र प्रदेश	9
बिहार	4
दिल्ली	3
गोवा	3
हरियाणा	12
कर्नाटक	11
केरल	3
महाराष्ट्र	37
नागालैंड	3
पंजाब	7
राजस्थान	3
तमिलनाडु	5
तेलंगाना	7
उत्तर प्रदेश	71
पश्चिम बंगाल	5

स्रोतः उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण(2016-17)